

दिवकत ♦ अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्राजील की फसल से दामों में हुई है कमी

चीनी निर्यातकों को दें पेनाल्टी से राहत : इस्मा

प्रेट्र ♦ नई दिल्ली

औद्योगिक संस्था इस्मा ने अपने निर्यात लक्ष्य में विफल रहने वाले निर्यातकों को लाइसेंस वापसी पर पेनाल्टी से राहत देने की मांग की है। इस्मा का कहना है कि चीनी निर्यात से कोई लाभ नहीं हो रहा है। घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी होने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट आने के कारण भारत से चीनी का निर्यात अब लाभदायक नहीं रह गया है। इसके कारण मिलों पर घरेलू कीमत से कम कीमत पर निर्यातित चीनी बेचने का दबाव बन गया है। इस्मा का कहना है कि अगर आरसी के तहत किए जा रहे निर्यात में दायित्व को कम कर दिया जाए तो इस दबाव से बचा जा सकता है।

इस्मा का कहना है कि निर्यातकों को सलाह दी जा रही है कि वे बिना पेनाल्टी के अपने लाइसेंस वापस कर दें। 3 अगस्त को डीजीएफटी ने 14.50 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। इसमें से नौ लाख टन चीनी फैक्ट्रियों से निर्यात के लिए भेजी जा चुकी है। अभी लगभग पांच



लाख टन चीनी निर्यात होना बाकी है। इस्मा ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस को बताया है कि कुछ चीनी मिल फिलहाल चीनी निर्यात करने के इच्छुक नहीं हैं। मिलों को निर्यात से ज्यादा कीमत घरेलू बाजार में मिल रही है।

शेष पांच लाख टन चीनी निर्यात के लाइसेंस वापस करने पर घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्राजील की फसल आ

जाने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट आ गई है जिसके कारण निर्यात अब फायदेमंद नहीं रहा है। उधर देश में सूखे की आशंका के चलते अगले सीजन में गन्ने का उत्पादन प्रभावित होने की खबरों के चलते घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। मेट्रो शहरों में चीनी की कीमत 37-45 रुपये प्रति किलो के आसपास हो गई है। चीनी निर्यात में ओपन जनरल

यथास्थिति

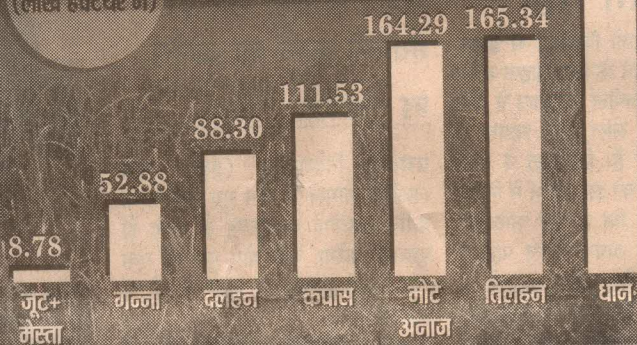
डीजीएफटी ने 14.50 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। इसमें से नौ लाख टन चीनी फैक्ट्रियों से निर्यात के लिए भेजी जा चुकी है। अभी लगभग पांच लाख टन चीनी निर्यात होना बाकी है।

उधर देश में सूखे की आशंका के चलते अगले सीजन में गन्ने का उत्पादन प्रभावित होने की खबरों के चलते घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं।

लाइसेंस लागू करने से पहले मार्केटिंग वर्ष 2011-12 के लिए सरकार ने 20 लाख टन चीनी निर्यात की मंजूरी दी थी। इस संबंध में खाद्य मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया था। इसका कारण देश में 260 लाख टन के बंपर चीनी उत्पादन होना था। ज्यादा उत्पादन होने के कारण ही चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई थी। हालांकि कुल मिलाकर 30 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था।

बुआई का रकबा (24.08.2012 को)

राष्ट्रीय सीजन
(लाख हेक्टेयर में)



पीटीआई ग्राफिक

विजयेंस भास्कर

27/8/12

✓